ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL (AUAB), M.P. CIRCLE, BHOPAL

Contact No. 9425076677

सादर प्रकाशनार्थ.....

बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन की राह पर...हड़ताल भी करेंगे

ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB) ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों से निम्नानुसार आंदोलन करने का आव्हान किया है। यह आंदोलन माननीय संचार राज्य मंत्री के साथ AUAB की 24.02.2018 को सम्पन्न मीटिंग में उनके द्वारा 01.01.2017 से 3rd PRC अनुसार वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन, 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, कर्मचारियों के वास्तविक मूल वेतन पर आधारित पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान और डायरेक्ट रिक्रूट कर्मियों को सुपरएन्युएशन का लाभ आदि मुद्दों पर दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के खिलाफ किया जा रहा है। इस देरी से कर्मचारी बेहद आक्रोशित है।

यह अत्यंत विचलित करने वाली स्थिति है कि माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पश्चात 8 माह की समयावधि बीत जाने के बावजूद DOT, जिन्हें इसका क्रियान्वयन करना है, ने अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन न कर DOT द्वारा बीएसएनएल के 1.85 लाख कार्यरत कर्मियों व लगभग 3.5 लाख रिटायर्ड कर्मियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

आंदोलन की रूपरेखा:

(1) परिमंडल और जिला स्तर पर **29.10.2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस** आयोजित कर मांगों को विस्तार से अवगत कराना।

(2) सभी स्तर पर **30.10.2018 को धरना।**

(3) परिमंडल व जिला स्तर पर **14.11.2018 को रैली।**

(4) डिमांड्स का **30.11.2018 तक निराकरण न होने की स्थिति में** सभी कर्मचारियों को गंभीर संघर्ष, जिसमें **हड़ताल** भी शामिल है, हेतु लामबंद किया जाए।

विभिन्न मुद्दों पर ब्रीफ नोट:

1. 01.01.2017 से तृतीय वेज रिवीजन...

बीएसएनएल कर्मी उन्हें 01.01.2017 से देय तृतीय वेज रिवीजन देने से इनकार किए जाने से बेहद हताश है। विगत 3 वर्षों से कंपनी द्वारा लाभ अर्जित नही किए जाने की वजह से तृतीय पे रिवीजन कमिटी की अनुशंसाओं में शामिल "एफोरडीबिलिटी क्लॉज़" की वजह से बीएसएनएल कर्मी वेज रिवीजन हेतु पात्र नही है।

यह एक सर्व विदित तथ्य है कि बीएसएनएल को 2007 से 2012 के बीच अपने नेटवर्क विस्तार हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीदी हेतु अनुमति प्रदत्त नही की गई। यही बीएसएनएल के लॉस में जाने का प्रमुख कारण है। CNBC TV 18 को 28.02.2015 को दिए गए इंटरव्यू में माननीय पूर्व संचार राज्य मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा भी यह कहा गया था कि **"BSNL और MTNL सन 2005-2006 तक करोड़ों के मुनाफे में थे। उसके बाद के वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई ? मैं खुले तौर पर यह कह सकता हूँ कि दोनों कंपनियों को विस्तार करने की अनुमति न मिले इस हेतु हर संभव प्रयास किए गए।"** यही है बीएसएनएल के घाटे में जाने की सही वजह।

किन्तु अब स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। सन 2013 पश्चात बीएसएनएल ने अपने मोबाइल नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है। इसके साथ ही कंपनी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव कर्मी भी कंपनी का राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विशेष प्रयास कर रहे हैं। कंपनी का राजस्व व ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उन्होंने **"कस्टमर डिलाइट ईयर" और "सर्विस विथ ए स्माइल"** जैसे अभियान चलाएं है। मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साझा प्रयासों की वजह से कंपनी के राजस्व व ग्राहक संख्या में आशाजनक वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए 2014-15 में बीएसएनएल का लॉस रु 8234 करोड़ था वहीं यह 2015-16 में घट कर रु 3880 करोड़ हो गया। बीएसएनएल ने रु 672 करोड़, रु 3854 करोड़ और रु 1684 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट भी क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17 में अर्जित किया है।

बीएसएनएल शनैः शनैः पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में 01.01.2017 से देय तृतीय वेज रिवीजन से इनकार की वजह से कर्मचारियों में बेहद हताशा है। निःसंदेह इसका असर उनकी उत्पादक क्षमता पर भी पड़ेगा और फलस्वरूप बीएसएनएल की रिवाइवल प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। यहां यह बताना भी मौजूं होगा कि बीएसएनएल बोर्ड ने भी कर्मचारियों को 15%फिटमेंट के साथ तृतीय वेज रिवीजन देने के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया है और वह भी सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग लिए बगैर। कर्मचारियों को वेज रिवीजन से इनकार न्याय संगत नही है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब सम्पूर्ण टेलीकॉम सेक्टर तनाव में है, लगभग सभी भारी लॉस की स्थिति में है और लाखों करोड़ों बैंक लोन की उन पर देनदारियां है। बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो सरकार के सामाजिक सरोकारों की पूर्ति कर रहा है। बीएसएनएल द्वारा सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे NOFN (Bharat Net), LWE प्रोजेक्ट, NFS प्रोजेक्ट आदि बगैर ज्यादा मुआवजे के बीएसएनएल के मानव संसाधन का उपयोग कर पूर्ण किए जा रहे है, जिसकी वजह से बीएसएनएल को अत्यधिक हानि हो रही है।

बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के नाम पर कर्मचारियों को HRA रिवीजन से इंकार न केवल अ-न्यायसंगत है बल्कि दिग्भ्रमित करने वाला भी है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सम्पूर्ण टेलीकॉम मार्किट में मची उथल पुथल रिलायंस जियो की प्रिडेटरी प्राइसिंग की वजह से है। यह भी नही भूलना चाहिए कि एयरटेल और वोडाफोन आईडिया जैसे बड़े ऑपरेटर्स भी हानि की स्थिति में पहुंच गए हैं। साथ ही, इन ऑपरेटर्स पर लाखों करोड़ों का भारी कर्ज भी है, जबकि तुलनात्मक रूप से बीएसएनएल का कर्ज नगण्य है, लगभग 10000

करोड़। हम यहां यह भी बताना चाहेंगे कि 2017 में एयरटेल, वोडाफोन और आईडिया की तुलना में मोबाइल सेगमेंट में बीएसएनएल की तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अलावा ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार भी रिलायंस जियो के अलावा बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने वर्ष 2017 में AGR में वृद्धि दर्ज की है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जून में समाप्त तिमाही में बीएसएनएल के AGR में 6.8% की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB) मांग करती है कि बीएसएनएल को 3rd PRC के एफोरडीबिलिटी क्लॉज़ से मुक्त कर बीएसएनएल बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार कर्मचारियों को 01.01.2017 से 15% फिटमेंट के साथ 3rd पे रिवीजन दिया जाए। AUAB के साथ 24.02.2018 को हुई मीटिंग में माननीय संचार राज्य मंत्री ने सहर्ष आश्वस्त किया था कि बीएसएनएल कर्मियों के वेज रिवीजन के निराकरण के लिए 3rd PRC में उल्लेखित "एफोरडीबिलिटी क्लॉज़" को शिथिल करने हेतु यूनियन कैबिनेट के विचारार्थ कैबिनेट नोट प्रस्तुत करने के लिए DOT द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किन्तु 8 माह की समयावधि बीत जाने के बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है।

2. बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन

बीएसएनएल द्वारा अभी तक 4G सेवा शुरू नही की गई है। सरकार द्वारा बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नही किए जाने से यह संभव नही हो पा रहा है। बीएसएनएल इसके लिए मार्किट प्राइस देने के लिए भी तैयार है।बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 4G स्पेक्ट्रम के लिए सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भी दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार स्पेक्ट्रम की 50% राशि बीएसएनएल देगा और 50% राशि कैपिटल इन्फ्यूजन के जरिए सरकार देगी। अन्य ऑपरेटर्स द्वारा 4G डेटा मार्किट में अपनी पैंठ बनाई जा रही है और ऐसे में 4G के अभाव में इनसे मुकाबला करना बीएसएनएल के लिए कठिन हो जाएगा। AUAB के साथ 24.02.2018 को हुई मीटिंग में माननीय संचार राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बीएसएनएल के प्रस्ताव अनुसार 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाएगा, किन्तु 8 माह पश्चात भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई है।

3. वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान

सरकार को DoPT के आदेश दिनांक 15.05.2000 को खारिज करते हुए 19.11.2009 को जारी आदेश अनुसार वेतनमान के अधिकतम की बजाय वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान किया जाना चाहिए। किन्तु DoT द्वारा 15.05.2000 के आदेश अनुसार ही बीएसएनएल को वेतनमान के अधिकतम पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन के भुगतान हेतु बाध्य किया जा रहा है। नवीनतम OM dated 19.11.2009 के अनुसार वेतनमान के अधिकतम की बजाय वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान किया जाना है । किंतु DoT इसे मान्य नही कर रहा है। विगत 11 वर्षों से बीएसएनएल को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। अभी तक लगभग 3500 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान बीएसएनएल द्वारा DoT को किया जा चुका है।

4. बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन रिवीजन

DoT में भर्ती हुए किन्तु बीएसएनएल से रिटायर होने वाले कर्मियों की पेंशन का रिवीजन 01.01.2017 से देय हो चुका है। वें CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 37 A के तहत भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फण्ड से पेंशन भुगतान के दायरे में आते हैं। पेंशन रिवीजन का वैसे भी बीएसएनएल कर्मियों के वेज रिवीजन या बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से कोई संबंध नही है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार

की है। 7वें वेतन आयोग ने बीएसएनएल के कर्मियों के लिए इस मुद्दे को महज इसलिए शामिल नही किया है कि बीएसएनएल कर्मियों को IDA पे स्केल दिया जाता है। इनकी पेंशन का पूर्व में रिवीजन 01.01.2007 से हुआ था, वह भी कैबिनेट के हस्तक्षेप के बाद। अतः हमारी मांग है कि सरकार बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन के रिवीजन के लिए तत्काल कदम उठाएं। 01.01.2007 से हुए विगत वेज रिवीजन के एग्जीक्यूटिव्ज के लिए आदेश 27.02.2009 को हुए थे जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के 07.05.2010 को। किन्तु बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन रिवीजन के आदेश काफी समय पश्चात 15.03.2011 को हुए। इस प्रकार की देरी इस बार नही होनी चाहिए। अतः बीएसएनएल से रिटायर्ड सरकारी पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन के लिए सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध है।

5. बीएसएनएल के डायरेक्ट रिक्रूट कर्मियों के लिए 30% सुपरएन्युएशन बेनिफिट्स के संबंध में 2nd PRC की अनुशंसाओं का अननुपालन

2nd PRC द्वारा अनुशंसा की गई थी कि सभी PSU अपने कर्मियों के लिए 30% सुपरएन्युएशन बेनिफिट्स लागू करें। यह अत्यंत खेदजनक है कि बीएसएनएल ने 2nd PRC की अनुशंसाएं पूर्ण रूप से लागू नही की है, जिससे से डायरेक्ट रिक्रूट कर्मियों को अपूरणीय क्षति हुई है। अतः यह मांग की जाती है कि इस मुद्दे का अविलंब निराकरण किया जाए।

प्रकाश शर्मा.....	**दत्ता मजूमदार..**	**हबीब खान.....**	**परवेज़ खान.....**	**देवेंद्र सैनी.....**	**आलोक नामदेव**
CS, BSNLEU	CS, SNEA	CS, NFTE	CS, AIBSNLEA	CS, AIGETOA	CS, SNATTA

Bhopal

29/10/2018